प्रारम्भ -

संविधान द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धान्तों और प्रशासनिक एवं प्रतिनिधिक संस्थाओं के एक संरचनात्मक ढाँचे की व्यवस्था की जाती है लेकिन यह संरचनात्मक ढाँचा व्यावहारिक राजनीति की परिस्थितियों से परिचालित होता है और उसमें निरंतर विकासशीलता की स्थिति होती है। व्यावहारिक राजनीति के तनाव और दबाव ही उसे सजीवता और शक्ति प्रदान करते हैं अथवा उसकी दुर्बलता के कारण बनते हैं।

भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण

भारत एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। मानव सभ्यता के 5000 वर्ष से भी पुराने इतिहास में कहीं भी, कभी भी इतने व्यापक पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रयोग नहीं चला, जैसा कि भारत में स्वाधीनता के बाद से चल रहा है। जनतंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता का अहसास पश्चिम से अधिक है। डा० रोस्टोव का यह कथन उल्लेखनीय है कि, "दूसरे महायुद्ध के बाद की सबसे आश्चर्यजनक घटना भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है।" प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० थॉम्पसन का कथन भी गौर करने लायक है, "भारत केवल स्वयं की दृष्टि से ही एक महत्वपूर्ण देश नहीं है वरन् वह समस्त विश्व में लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। ऐसी स्थिति में यदि भारत कभी पुनः निरंकुश पंजों में जकड़ा जाता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी।"

दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धान्तिक विचार-विमर्श के लिए प्रश्न और आधार

Scanned with CamScan

सामग्री लेने या छोड़ने का निश्चय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धान्त कहलाता है। कुछ लोग सिद्धान्त शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे 'व्याख्या की चरम परिणति' कहकर पुकारते हैं।

- इजाक के अनुसार," दृष्टिकोण राजनीतिक गवेषणा में, राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामान्य रणनीति या व्यूहरचना (Strategy) है।

मर्टन के अनुसार," दृष्टिकोण में संवर्गीकरण (Categorization), वर्गीकरण (Classification) तथा परिभाषा (Definition) को आधार बनाकर राजनीतिक तथ्यों को क्रमबद्ध किया जाता है।

- दृष्टिकोण विचार चित्र (Paradigm) की तुलना में अधिक व्यापक होता है।

हास एवं कहील के अनुसार इसमें विचारचित्र एवं अवधारणात्मक परियोजना दोनों ही शामिल होती हैं।

- दृष्टिकोण पूर्णतः विश्लेषणात्मक होता है।

अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण -

(i) - भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण
(ii) - —— —— ऐतिहासिक दृष्टिकोण
(iii) - —— —— संस्थानात्मक दृष्टिकोण
(iv) - —— —— समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
(v) - —— —— व्यवहारवादी दृष्टिकोण
(vi) - —— —— राजनीतिक विकास दृष्टिकोण
(vii) - —— —— मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण
(viii) - गांधीवादी दृष्टिकोण
(ix) - मार्क्सवादी दृष्टिकोण

Scanned with CamScanner

> भारतीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी दृष्टिकोण → कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक संविधान के प्रावधानों की व्याख्या पर बल देते हैं। वे भारत की राजनीतिक समस्याओं को भी कानूनी - संवैधानिक वैधता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं।

1- Granville Austin - The Indian Constitution: Corner Stone of a Nation (1966)
2- Allen Gledhill - The Republic of India (1951)
3- D.D. Basu - Commentary on the Constitution of India (~~1949~~) (1955)
4- B.N. Rao - Indias Constitution in the Making (1960)

> ऐतिहासिक दृष्टिकोण → इस दृष्टिकोण के पीछे मान्यता यह है कि वर्तमान अतीत का फल है, अतः इसे अतीत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को भली भाँति समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में झांकना होगा।

1- A.B. Keith - Constitutional History of India (1963)
2- V.P. Menon - The Transfer of Power in India (1957)
3- V.P. Menon - The Integration of Indian States (1956)
4- Maulana Azad - India Wins freedom (1988)
5- Raj Mohan Gandhi - India Wins Errors (1989)
6- Subhash C. Kashyap - History of the Parliament of India (1994)
7- M. Brecher - Nehru - A Political Biography (1959)
8- Moris Jones - The Government and Politics of India (1974)

→ ऐतिहासिक अध्ययन आसान है, क्योंकि अध्ययन सामग्री आसानी से जुटाई जा सकती है। इसमें खतरा यह बना रहता है कि अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत कर सकता है।

> संस्थानात्मक दृष्टिकोण → इसके समर्थक मानते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं ही हमारे राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती हैं। वस्तुतः ये वैध एवं औपचारिक संस्थाओं जैसे - ~~राष्ट्र~~ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री

Scanned with CamScanner

संसद, राज्यपाल आदि के पद एवं भूमिका के अध्ययन पर बल देते हैं।

1- Madhu Limaye - Cabinet Government in India (1967)
2- Morris Jones - Parliament in India (1957)
3- J.R. Siwach - The Indian President (1971)
4- Subhash C. Kashyap - Our Parliament (1989)

- वस्तुतः इन अध्येताओं ने भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संरचनात्मक (Structural) दृष्टि से ही किया है और उनमें प्रकार्यात्मक पहलू (Functional Aspect) की उपेक्षा की गयी है।

→ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण → कैटलिन ने तो स्पष्ट कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है और इसलिए समाजशास्त्र को इससे अलग नहीं किया जा सकता। यह बात सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व संस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती है। अतः राजनीति में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक सन्दर्भ में ही उचित प्रकार से हो सकता है।

1- Rajni Kothari - Cast in Indian Politics (1970)
2- F.G. Bailey - Politics and Social Change (1963)
3- Loyed and Susan Rudolf - The Modernity of Trandition (1967)
4- R. Bhaskaran - Sociology of Politics (1967)

- भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में जो अध्ययन हुए हैं उनमें जहाँ एक ओर यह दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि "सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक प्रवृत्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है (नॉर्मन डी पामर, फिलिप्स), वहीं दूसरी ओर यह भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक प्रवृत्तियों को मोड़ने में सक्षम है (रजनी कोठारी, रूडोल्फ)

Scanned with CamScanner

→ भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी अध्ययन → व्यवहारवादी उपागम

विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार, "व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान क्रमबद्ध हो और अनुभवात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाय।"

1- A.H. Somjee - Voting Behaviour in an Indian Villege (1959)
2- V.M. Sirsikar - Political Behaviour in India (1965)
3- S.P. Verma and Iqbal Narayan - Voting Behaviour in a Changing Society (1972)
4- V.M. Sirsikar - Sovereign without Crowns (1981)
5- I. Ahmed - Muslim Political Behaviour (1975)

- मतदान व्यवहार के इन अध्ययनों से भारतीय राजनीति के अंतरंग को समझने में काफी सहायता मिलती है। इससे पता चलता है कि भारत की वर्ग संरचना ने भी चुनावों को किस प्रकार प्रभावित किया है। चुनावों में जाति, सम्पत्ति, व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीयता की भूमिका का स्पष्टीकरण भी इन अध्ययनों से होता है।

→ भारतीय राजनीति के अध्ययन का राजनीतिक विकास दृष्टिकोण →

एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों में होने वाले उलट-फेर और परिवर्तन को समझने के लिए 'राजनीतिक विकास' का विचार विकसित किया गया। इसके अर्थ को लेकर विचारकों में मतभेद बना हुआ है। उदाहरण के लिए, स्पर्ट, एमर्सन, लिपसेट, कोलमैन और कार्टराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्वशर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है जबकि रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्री ने इसको औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है।

Scanned with CamScan

गुन्नार मिर्डल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है। बिंडर इसको राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या संघटक मानता है। फ्रेड रिग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासनिक एवं कानूनी विकास के आधार पर की है।। डॉयच ने इसको जनसंचारण और जनसहभागिता माना है। आमण्ड एवं कोलमैन राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का पर्याय कहते हैं। ब्लेक, आइजनस्टेड एवं कॉर्न होजर ने इसे सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशायुक्त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में विवेचित किया है।

भारत जैसे देश में (नवस्वतंत्र) राजनीतिक विकास का अर्थ यह होता है कि एक प्राचीन देश अपनी पुरानी परम्परा और विविधता को बनाए रखते हुए, आधुनिक युग की सबसे अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। भारत में राजनीति मुख्यतः देश की एकता को बनाये रखने की राजनीति है।

1- Myron Weiner - The Politics of Scarecity (1963) दबाव समूहें का अध्ययन
2- Myron Weiner - State Politics in India (1968)
3- Iqbal Narayan - State Politics in India (1967)
4- Marcus Franda - West Bengal ~~and~~ federalising Process in India
5- Daya Krishna - Political Development in India (1979)
6- Rajni Kothari - State and Nation Building (1976)
7- Morris Jones - The Government and Politics of India (1974)
8- Atul Kohli - Democracy and Discontent: Crisis of Governability in India - (1991)

Scanned with CamScanner

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन ⇒ इस दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति के बहुत कम अध्ययन हुए हैं। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण से अधिक सम्बन्धित रहा है। यह दृष्टिकोण 'फील्ड वर्क' और अवलोकन पर बल देता है। अध्ययन-कर्ता जिस सामाजिक और राजनीतिक इकाई का अध्ययन करता है, उसमें घुल मिल जाता है, उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज और वेशभूषा अपना लेता है और बाद में अपने अनुभवों को ~~अपना लिखता~~ है

1- F.G. Bailey - Politics and Social Change in Orissa (1959)
2- A.H. Somjee - Voting Behaviour in a Village (1959)
3- S.C. Dubey - Indian Village (1955)
4- Yogesh Atal - Local Communities and National Politics (1971)

- गांधीवादी दृष्टिकोण ⇒ इस दृष्टिकोण के अनुसार पश्चिम के औजारों से भारतीय जनजीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। वैकल्पिक ढांचे की तलाश में डा० मेहता ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्नाइजेशन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया' में संसदीय व्यवस्था के औचित्य पर प्रश्न व्यापक रूप से उठाया है। डा० मेहता गांधीवादी व्यवस्था को भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट पाते हैं। गांधीवादी चिंतक श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने भी अपने लेखों एवं ग्रंथों के माध्यम से गांधीवादी दृष्टि से भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया है

» भारतीय राजनीति के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण ⇒ मार्क्सवादी विचारकों का मत है कि पश्चिमी लेखकों द्वारा प्रतिपादित उपागम नये राज्यों की राजनीति का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे हैं। ये राज्य की औपचारिक संरचनाओं को बहुत कम महत्व देते हैं। ये सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को सर्वोच्चता

Scanned with CamScanner

प्रदान करते हैं। वे मानते हैं कि समाज में आर्थिक शक्ति से सम्पन्न वर्ग का प्रभुत्व रहता है।

1- Rajni Pamdutt - आज का भारत (1970)
2- अयोध्यासिंह - भारत का मुक्तिसंग्राम (1977)
3- A.R. Desai - Social Background of Indian Nationalism (1977)
4- ए. आर देसाई - भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ (1978)
5- V. R. Mehta - Ideology, Modernization and Politics in India (1983)

- स्वाधीनता आन्दोलन को लेकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं लेकिन इनमें से कोई भी पुस्तक इस बात को रेखांकित करने का प्रयास नहीं करती कि इन आन्दोलनों में भारत के बहुसंख्यक मजदूर, किसान, जनता तथा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। अयोध्या सिंह की पुस्तक इस विषय पर अपने ढंग की पहली पुस्तक है। 'A.R. देसाई' भारतीय संविधान को बुर्जुआ संविधान मानते हैं। वे कहते हैं कि वह राज्य जो काम के अधिकार की गारण्टी नहीं देता, प्रारम्भ से ही सम्पत्तिहीन वर्गों का प्रतिनिधि कहलाने के अपने दावे को खो देता है।

'वी. आर. मेहता' मानते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा ने समाज में स्थित विषमता, शोषण, आदि को स्पष्टतः उजागर किया है किन्तु चूँकि भारतीय समाज की उनकी ~~व्याख्या~~ व्याख्या अंशतः ही सही है, इसलिए वे शासनतंत्र पर छा नहीं सके।

Scanned with CamScan

1- Name of The Teacher and Department
- Rajkumar, Political Science Department

2- Class and Year / Semester - M.A. I Semester, MA III Semester
and - MA. I Year, II Year

3- Code of the Paper - G-1072

4- Name of The Paper - Indian Political System - I Semester
- State Politics in India - III Sem

5- Topic of E-Content - भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण

6- Date of E-Content - 18, July - 2020

Scanned with CamScanner